>

Title: Difficulties being faced by telephone and mobile consumers in the country.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से और बड़े दुख से यह बात सदन में कहना चाहता हूं। केन्द्र सरकार का टेलीकम्युनिकेशन विभाग बहुत बड़ा विभाग है। कुछ समय पहले हम पांच-सात सांसद, जो अलग-अलग दलों से थे, बातें कर रहे थे। सभी माननीय सदस्य एक बात पर जोर दे रहे थे कि सांसदों को मोबाइल फोन के लिए जो सिम कार्ड दिए गए हैं, वे वापस हो जाएं, तो बहुत अच्छा हो। मेरी भावना भी यही थी। हमें जो सिम कार्ड फोन कनेक्टिविटी के लिए दिया गया है, वह बीएसएनएल की तरफ से दिया गया है। यह सिम कार्ड आप के पास और हम सबके पास है। अगर मैं अपने मोबाइल से उस सिम कार्ड से जरिए बात करना चाहूं तो पहली बार में बात हो ही नहीं सकती। दूसरी बार कोशिश करने का सवाल पैदा नहीं होता, तीसरी कोशिश की बारी ही नहीं आती और चौथी कोशिश का तो राम ही भरोसे है। यह सब बीएसएनएल की तरफ से एक साजिश के तहत हो रहा है। जहां कहीं टॉवर लगाने की बात आती है तो सबसे पहले एयर टैल, वोडाफोन, एयर सैल, रिलायंस आदि के टॉवर लगते हैं, फिर सबके बाद में बीएसएनएल की बारी आती है। जब सारी निजी कम्पनीज के सिम कार्ड्स बिक जाते हैं, तो हमारी बीएसएनल के सिम कार्ड्स पड़े रहते हैं और हमें दिए जाते है। इसके बाद फ्रिक्वेंसी की बात आती है, तो सबसे कमजोर फ्रिक्वेंसी बीएसएनएल की है और यह सब एक बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। जब कभी इस मसले पर विचार विमर्श की बात होती है तो सांसदों से इस बारे में कोई राय नहीं ली जाती है। फ्रिक्वेंसी का जहां तक सवाल है, तो यह एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, इसमें भी ड्रामा है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जब कहीं टॉवर लगाने की बात आती है तो प्राइवेट ऑपरेटर और सरकारी भी किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम पर ले लेते हैं। उस जमीन पर ये लोग टॉवर लगाते हैं, अपने इम्प्लाइज रखते हैं और अपना चौकीदार बिठाते हैं। किसान को कुछ नहीं दिया जाता है, जबकि उसकी जमीन मुफ्त ली जाती है।

सभापति जी, आपको याद होगा, जब एयर टेल की कॉल रेट 30 से 34 रुपए प्रति मिनट थी, उस वक्त बीएसएनएल आई और उसने एक-दो रुपए प्रति मिनट कॉल रेट कर दी, जिससे सभी निजी सर्विस ऑपरेटर्स ने अपनी कॉल रेट में कमी की। लेकिन हमारा मंत्रालय चाहता है...(व्यवधान) कि धीरे-धीरे यह विभाग बंद हो जाए और सारी कॉल्स दोबारा प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास चली जाएं, जिससे वे अपने हिसाब से कॉल रेट की दरें फिक्स कर सकें। हमारे देश में 5,93,601 गांव हैं, जो पापुलेटेड हैं, इनहैबिटेंट्स हैं। जो इन्होंने कहा है, उसके अनुसार 5,62,152 कवर कर दिए। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में, यहां डॉ. फारुक अब्दुल्ला साहेब बैठे हैं, वह हमारे लीडर हैं, वह भी जानते हैं, नारबन में, बारबन में, दक्षण में, सतारी में, गंधारी में, पाडर में, डुडू में, वसंतगढ़ में, लाटी में, टूंडा में कहां कवरेज हुई है। ये मैं दूर-दराज इलाकों की बात कर रहा हूं। हजारों-हजार गांव अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, कवर नहीं हुए हैं, तो फिर ये डेटा कहां से आ गया।

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): Sir, I would like to assure the hon. Member that as soon as the House is over, I will request the hon. Minister of IT to go to these areas with the hon. Member of Parliament, to see himself what the conditions are; and we in the Government of India, will try to help all these backward areas to get telephone connections.

MR. CHAIRMAN : All right. Now, Shri Mahendrasinh Chauhan.

...(*Interruptions*)

चौधरी लाल सिंह : मेरा आखिरी सब्मिशन है, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Lal Singhji, very unusually, you got a reply also in between your submission. You should be satisfied, now.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Mahendrasinh Chauhan, I have called your name. You continue, please.

...(*Interruptions*)

चौधरी लाल सिंह : सर, आप मेरी बात सुनें। मंत्री साहेब के आश्वासन...(व्यवधान)

MR CHAIRMAN: Mr. Lal Singh, please take your seat.

...(*Interruptions*)

चौधरी लाल सिंह : मैं मंत्री जी की बात से तो खुश हूं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Lal Singh, this is not going on record. Please take your seat.

*(Interruptions) â€¦ **

* Not recorded.